



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072020-220445
CG-DL-E-09072020-220445

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]
No. 332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2020/आषाढ़ 18, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, 9 JULY, 2020/ASHADHA 18, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

सं. 18/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 435(अ).—जहां, कि दक्षिण अफ्रीका में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'फिनाँल' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 10 जुलाई, 2015, जिसे सा.का.नि. 552(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/25/2019-डीजीटीआर, दिनांक 27 दिसंबर, 2019, जिसे दिनांक 27 दिसंबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिनपश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है), के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त प्रतिपाटन शुल्क को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार छः माह की और अवधि तक जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 10 जुलाई, 2015, जिसे सा.का.नि. 552(अ), दिनांक 10 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अन्तः स्थापित किया जाएगा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क 9 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, जारी रहेगा।”

[फा. सं. 354/124/2002-टीआरयू (पीटी. V)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2020

No. 18/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 435(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/25/2019-DGTR dated the 27th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th December, 2019, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Phenol’ originating in or exported from South Africa, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 32/2015-Customs (ADD) dated the 10th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 552(E) dated the 10th July, 2015, and has requested for extension of the said anti-dumping duty for a period of six months in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2015-Customs (ADD) dated the 10th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 552(E) dated the 10th July, 2015, namely-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 9th January, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 354/124/2002-TRU (Pt-V)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.